

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

अपील संख्या

13/13/2021

राजि० न०

2021/146

प्रवेश तिथि

08.10.2021

निर्णय दिनांक

20.01.2025

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ अलवर जरिये विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़।

—निगरानीकार

## बनाम

1. गोपीराम पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम बडोदा मेव पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज०।

2. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ अलवर जरिये सचिव/सरपंच।

—गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बडोदा मेव दिनांक 10.01.13 पट्टा संख्या 36।

उपस्थित:—

01. श्री अशोक शर्मा

— वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बडोदा मेव दिनांक 10.01.13 पट्टा संख्या 36 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि गैरनिगरानीकार सं. 1 गोपीराम ने गैरनिगरानीकार सं० 2 के समक्ष कृषि भूमि में रिहायशी मकान हेतु पट्टा दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर गैर निगरानीकार सं० 2 ने प्रस्ताव पास कर गैरनिगरानीकार सं० 1 को दिनांक 10.01.13 को आदेश पारित कर 299 वर्ग गज भूमि हेतु पट्टा जारी किया गया इस बाबत शुल्क तौर पर गोपीराम से 200 /—रूपये की राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई।

गैरनिगरानीकार सं० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरुद्ध जारी किया है तथा पंचायती राज० अधि० व राजस्थान पंचायती राज० नियमों की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय ना तो कृषि भूमि पर किये पर किये गये किसी निर्माण की जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूमि पर जो निर्माण है। यह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से संबंधित कोई तथ्य तथा भूमि के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही जहां भूमि स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अंकित किया गया है तथा भूमि के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नहीं किया गया है कि अमुक निर्माण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नहीं किया गया है तथा नियमानुसार कृषि भूमि में पट्टे जारी करने का ग्राम पंचायत के अधिकार कुछ सीमा तक ही है जबकि गैरनिगरानीकार सं० 1 उन अधिकारों की सीमा में नहीं आता है उक्त पट्टा गैरकानूनी रूप से दिया हुआ है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

भूखण्ड हेतु नियमन पट्टा जारी करने हेतु जो उज्जदारी नोटिस निकाला गया है उसमें भी भूमि निर्माण जिसका पट्टा जारी किया जाना है की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नहीं किया है ताकि उज्जदार सम्पति/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उजदारी करने या करने की स्थिति पर विचार ना कर सके ना ही उजदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चरपा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उजदारी नोटिस को सर्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला ही अपने विवादित आदेश में लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनेदखी करते हुये जारी किया गया है जिस को मान्य करार नहीं दिया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उसे जांच में भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई उक्त पट्टा किस खसरा न० में जारी किया गया यह भी पट्टे में नहीं दर्शाया गया है। गैरनिगरानीकार स० 1 ने गैरनिगरानीकार स० 2 से मिलित कर गलत प्रकार से उक्त पट्टा जारी कराया गया है। निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम की धारा 97(1) में निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधान नहीं है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनांक 10.01.13 पट्टा स० 036 जो ग्राम पंचायत बडौदा द्वारा जारी किया गया को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा आवासीय पट्टा दिलाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत बडौदामेव को लिखे गए प्रार्थना पत्र के अनुसार गैरनिगरानीकार संख्या 01 के मकान के पास ही स्थित कृषि भूमि भी है इसलिए कृषि भण्डारण हेतु पट्टे की आवश्यकता हेतु निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत बडौदा मेव द्वारा पट्टा जारी करते समय ना तो कृषि भूमि पर किये पर किये गये किसी निर्माण की जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की कोई जानकारी की। प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि हेतु पट्टा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 में पुराने गृहों को नियमित किये जाने का प्रावधान है जिसमें 300 वर्गगज से अधिक के गृह नियमित नहीं किया जाता तथा उस पर न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण होना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा कृषि भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। उक्त पट्टा जारी करने में पंचायतीराज नियम के नियम 157 एवं अन्य नियमों का भी उल्लंघन पाया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधिवत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2013 में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनिगरानीकार संख्या 02 (ग्राम पंचायत बडौदा मेव) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2013 पट्टा संख्या 036 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

